

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 58 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रजत मालू पुत्र ओमप्रकाश मालू जाति माहेश्वरी (महाजन) निवासी सदर बाजार, वैकटेश सत्यनारायण मंदिर के सामने, वार्ड नं. 4, डेगाना जिला नागौर बहैसियत खुद एवं बहैसियत आम मुख्त्यार सोहनी देवी पत्नी गंगाधर, ओमप्रकाश पुत्र गंगाधर जातियान माहेश्वरी (महाजन) निवासीगण सदर बाजार, वैकटेश सत्यनारायण मंदिर के सामने, वार्ड नं. 4 डेगाना जिला नागौर।		1अधिशायी अधिकारी, नगरपालिका डेगाना। 2बालकिशन पुत्र जवाराराम 3शांतिलाल पुत्र जवाराराम जातियान ब्राह्मण निवासीगण गौरेडीचांचा, तहसील डेगाना जिला नागौर।

उपस्थिति-

1. श्री अशोक चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री पवन श्रीमाली, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
3. श्री ठाकुर प्रसाद राठी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

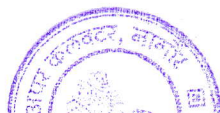
निर्णय

दिनांक 01.08.19

1- यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोरेडीचांचा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 बालकिशन व 3 शांतिलाल की माता श्रीमती केसर देवी के पक्ष में मिसल सं. 396/2001-02 दायर दिनांक 5.4.01 के जारी पट्टा सं. 125 दिनांक 24.12.01 को जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 11.07.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री पवन श्रीमाली अधिवक्ता तथा अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से श्री ठाकुर प्रसाद राठी अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में ग्राम पंचायत गोरेडीचांचा के पट्टा सं. 125 दिनांक 24.12.01 की फोटोप्रति, पट्टा विलेख बहक गंगाधर मालू एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, वसीयतनामा केसर देवी बहक बालकिशन व अन्य की फोटोप्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र केसर देवी की फोटोप्रति, बंटवाडा भूखण्ड बालकिशन एवं शांतिलाल की फोटोप्रति, प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पोस्टल ऑर्डर की फोटोप्रति, नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, नामान्तरण कार्यवाही हेतु नगरपालिका डेगाना में दिनांक 10.05.18 से लंबित पत्रावली की फोटोप्रति पेश की गई एवं दिनांक 29.07.19 को पत्रावली सं. 1323/2018-19 आवेदक शांतिलाल शर्मा नगरपालिका मंडल डेगाना की फोटोप्रति एवं भू खण्ड पर पहले से निर्मित कमरे की फोटो पेश की गई है जबकि अप्रार्थी द्वारा मौके की छ फोटो, बैक खाते की डिटेल्, आधार शांतिलाल की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत गोरेडी चांचा के पट्टा सं. 125 की फोटोप्रति, नामान्तरकरण आदेश बहक शांतिलाल द्वारा नगरपालिका डेगाना दिनांक 11.01.19 की फोटोप्रति, राशन कार्ड शांतिलाल की फोटोप्रति, नगरपालिका रसीद दिनांक 23.05.18, 04.01.19, 06.03.19, 13.05.19 व 28.06.19 की फोटोप्रतियां, राशन कार्ड बालकिशन वर्ष 1995-96 की फोटोप्रति, नगरपालिका डेगाना द्वारा आपति आमत्रण सूचना की फोटोप्रति, राशन कार्ड केसर देवी दिनांक 07.08.01 की फोटोप्रति, विद्युत बिल जवाहरलाल दिनांक 17.06.98 की फोटोप्रति, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की रसीद सं. 47 की फोटोप्रति, टेलीफोन बिल शांतिलाल शर्मा की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकॉर्ड मिसल सं. 396/2001-02 दायर दिनांक 5.4.01, पट्टा सं. 125 व इससे संबंधित पत्रावली अधिशायी अधिकारी डेगाना से मंगाया गया जिन्होंने अपने पत्र क्रमांक नपा डेगाना/2019-20/1113 दिनांक 23.07.19 के द्वारा मूल पट्टा सं. 125 प्रस्तुत किया गया है तथा ग्राम पंचायत गोरेडी चांचा द्वारा पत्रावली सुपुर्द नहीं किया जाना बताया गया। प्रार्थी द्वारा निगरानी के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से दिनांक 23.07.19 को जवाब प्रस्तुत किया गया।

2- उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी है कि -

2(1)-प्रार्थी की पुश्तेनी जायदाद नगरपालिका क्षेत्र डेगाना में स्थित है। जो क्षेत्र पूर्व में ग्राम पंचायत गोरेडी चांचा में आता था। जहां प्रार्थी की पुश्तेनी भूमि का पट्टा विलेख प्रार्थी के दादा गंगाधर के नाम से तहसीलदार द्वारा



अपर कलक्टर, नागौर

दिनांक 24.03.53 को जारी किया गया। प्रार्थी के दादा के यहां अप्रार्थी सं. 2 व 3 की माता केसर देवी घरेलु कार्य करते रहने से उसके रहवास हेतु उक्त पट्टासुद भूमि में से सड़क की तरफ का भूखण्ड व निर्मित कमरा रहवास हेतु दिया। जहां अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने प्रार्थी के दादा की पट्टासुद भूमि को हड़पने की योजना बनाकर अपनी माता केसर देवी जो उस भूमि में रह रही थी, का पट्टा बनाने के लिये तत्कालीन सरपंच से मिलीभगत कर भूमि को अपनी कब्जासुद होना बताकर 4455 वर्गफुट भूमि का पट्टा केसर देवी के नाम से जारी करवा लिया। उक्त पट्टा प्रार्थी के दादा के नाम जारी पट्टासुद भूमि का दुबारा पट्टा अनाधिकृत तरीके से जारी होने पर निरस्त करवाने के लिये निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2(2)—प्रार्थी की पट्टासुद सम्पत्ति वार्ड सं. 4 डेगाना जिला नागौर में आई हुई है। जिसका पट्टा विलेख राज. पंचायत राज अधिनियम, 1959 प्रभाव में आने से पूर्व दिनांक 24.03.53 (संवत् 2009 चैत्र सुदी दशम) को प्रार्थी के दादा गंगाधर पुत्र कन्हैयालाल माहेश्वरी, निवासी डेगाना के नाम से तत्कालीन तहसीलदार मेडता के द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर नागौर के आदेशानुसार जारी किया गया था, जिसके पट्टा सं. 302/52-53, मिसल सं. 69 है। उक्त पट्टे के नाप गज में दर्ज है।

2(3)—उक्त पट्टासुदा जायदाद में से प्रार्थी के दादा के द्वारा अपने जीवनकाल में पूर्वी दिशा की तरफ यानि आम रास्ता (स्टेशन जाने वाली सड़क) की तरफ मकान का निर्माण करवाया गया था तथा पश्चिम हिस्सा खाली पड़ा था, जिसे प्रार्थी के दादा ने अपने यहां काम करने वाली श्रीमती केसर देवी, जो अप्रार्थी सं. 2 व 3 की माता है, को रहवास हेतु दिया हुआ था। श्रीमती केसर देवी का जहां पर रहवास आया हुआ है, वहां प्रार्थी के दादा ने दो कमरे अपने मकान से अलग रहवास हेतु दिये हुए थे, जिसमें केसर देवी अपने परिवार सहित रहती थी तथा अप्रार्थी सं. 2 व 3 भी वही पर रहते थे।

2(4)—प्रार्थी के दादा गंगाधर जी जो कि डेगाना व आस पास के क्षेत्र में बहुत बड़े भामाशाह होने के कारण उनके द्वारा क्षेत्र में कई विद्यालय, अस्पताल बनवाये थे तथा उनके द्वारा ही अप्रार्थी सं. 2 व 3 की माता श्रीमती केसर देवी, जो कि प्रार्थी के दादा के यहां काम करती थी, की गरीबी अवस्था को देखते हुए उन्हें अपने स्वयं के पट्टा सुदा भूखण्ड में से कुछ हिस्सा, जिस पर कमरा निर्मित किया हुआ है, निवास हेतु दिया गया था। अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने इसका नाजायज फायदा उठा कर प्रार्थी के दादा की पट्टा सुदा भूमि को अपनी कब्जा सुदा बताकर तत्कालीन सरपंच गोरेडी चांचा से मिली भगत करके निगरानीधीन पट्टा जारी करवा लिया, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2(5)—ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व निर्धारित औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया। यदि ग्राम पंचायत के द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं का पालन किया जाता तो उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व ही प्रार्थी के दादा के नाम से जारी पट्टे की जानकारी हो जाती, तथा श्रीमती केसर देवी के नाम से किये गये आवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत कर दी जाती, परंतु सरपंच के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 व 3 से मिलीभगत करके बिना औपचारिकतायें पूर्ण किये बाले-बाले ही पट्टा जारी कर दिया, जो वैधानिक औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना जारी किया हुआ होने से उक्त पट्टा विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2(6)—उक्त पट्टा जारी करने के पूर्व तत्कालीन ग्राम पंचायत को नियमानुसार भूमि का मौका निरीक्षण करने हेतु कमेटी गठित करके मौका रिपोर्ट मंगवाई जानी आवश्यक थी तथा मौका रिपोर्ट सकारात्मक आने पर ही उक्त पट्टे बाबत गांव के सार्वजनिक दर्शमान स्थान पर पट्टे के आवेदन संबंधित सूचना चस्पा की जाती तथा उक्त सूचना सार्वजनिक दर्शमान किये जाने के पश्चात् एक माह तक उक्त आवेदन पर आपत्तियां मांगी जाती, तत्पश्चात् ही पट्टा जारी किया जाता, परंतु तत्कालीन सरपंच के द्वारा ऐसा नहीं करके बाले-बाले ही पट्टा जारी कर दिया, जिसके कारण उक्त निगरानीधीन पट्टे के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी, और उक्त पट्टा बिना कोई सूचना चस्पा किये एवं नियमानुसार औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना जारी किया हुआ होने से उक्त निगरानीधीन पट्टा निरस्तनीय है।

2(7)—अप्रार्थी सं. 2 व 3 के द्वारा उक्त पट्टे दस्तावेजों का वैधानिक रूप से पुराने समय में जारी किये हुए होने बताने के लिये उक्त पट्टे को केसरी देवी के स्वर्गवास के पश्चात् पश्चातवर्ती तारीखों में सरपंच से मिली भगत करके जारी करवाया, इसी कारण उक्त पट्टे के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई मिसल रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी के द्वारा निगरानीधीन पट्टे से संबंधित दस्तावेज प्राप्त हेतु नगरपालिका डेगाना में आवेदन करने पर यह ज्ञात हुआ कि नगरपालिका डेगाना में जब ग्राम पंचायत गोरेडीचांचा के पट्टों से संबंधित रिकॉर्ड का हस्तान्तरण नहीं हुआ है, यानि की नगरपालिका डेगाना निगरानीधीन पट्टे की कोई मिसल उपलब्ध नहीं है, अर्थात् तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत गोरेडीचांचा के द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व किसी भी प्रकार की मिसल का संधारण नहीं किया और पश्चातवर्ती तारीखों में पट्टे के प्रारूप में पट्टा जारी कर दिया। जबकि इस बाबत न तो आवेदन पत्र, मौका रिपोर्ट, आवेदित क्षेत्र का नक्शा, राशि जमा की रसीद तथा आपत्तियां आमन्त्रित करने बाबत नोटिस चस्पानगी का कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं है। यहां तक कि पट्टे में वर्णित ग्राम पंचायत का संकल्प (प्रस्ताव) भी प्रस्ताव रजिस्टर में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि तत्कालीन सरपंच, गोरेडी चांचा ने अप्रार्थी सं.



2 व 3 से मिली भगत करके प्रार्थी के दादा के नाम से जारी पट्टा सुदा भूमि को हडप करने के उद्देश्य से उक्त निगरानीधीन पट्टा प्राप्त किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

2(8)-हाल ही में अप्रार्थी सं. 2 व 3 के द्वारा प्रार्थी की पुश्तैनी पट्टासुदा भूमि पर दुकानों का निर्माण कार्य करवाना प्रारंभ किया, तब प्रार्थी ने निर्माण कार्य करने से रोका और उन्हें पूछा कि आपको उक्त भूखण्ड पर निर्माण करने ईजाजत मेरे द्वारा नहीं दी गई है, तो आप निर्माण कार्य नहीं करवा सकते हो। तब अप्रार्थी सं. 2 व 3 के द्वारा प्रार्थी को यह बताया गया कि हमने सरपंच से मिली भगत करके पट्टा प्राप्त कर लिया है, अब यह भूमि तुम्हारी नहीं रही है, इसलिये हमारे कार्य में दखल अंदाजी मत करो, हम तो निर्माण करवाके ही रहेगे। इस प्रार्थी ने नगरपालिका डेगाना में अप्रार्थी सं. 2 व 3 के द्वारा बताये गये तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने हेतु नगरपालिका डेगाना में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन किया गया, तब दिनांक 24.06.19 को प्रार्थी को निगरानीधीन पट्टे की जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थी को यह ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी सं. 2 व 3 के द्वारा प्रार्थी की पुश्तैनी पट्टासुदा भूमि में स्थित मकान की पश्चिमी दिशा में रिक्त पडी भूमि का तत्कालीन सरपंच गोरेडी चांचा से मिली भगत करते हुए पट्टा प्राप्त कर लिया, जो पट्टा पूर्णतया फर्जी एव कूटरचित है, जो नियमों के विपरीत जारी किया हुआ है, जो कानूनन निरस्तनीय है।

2(9)-प्रार्थी को उक्त पट्टे की वास्तविक जानकारी दिनांक 24.06.19 को हुई, जब प्रार्थी के द्वारा सूचना का अधिनियम आवेदन नगर पालिका में दिया और अप्रार्थी सं. 2 व 3 की माता के नाम से जारी पट्टे की जानकारी हुई, उसी दिनांक को उक्त निगरानीधीन पट्टे की जानकारी होने से जानकारी दिनांक से प्रार्थी के द्वारा यह निगरानीधीन याचिका अंदर मियाद प्रस्तुत की गई। इस संबंध में माननीय राज. उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका सं. 365/17, अनवान प्रकाशचंद मीणा बनाम संजय भारती वगैरा में पारित आदेश दिनांक 19.01.17 के द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि जानकारी की दिनांक से मियाद की गणना की जायेगी। प्रार्थी के द्वारा अपनी निगरानी याचिका में जानकारी का तथ्य दिनांक 24.06.19 को होना अंकित किया है तथा दिनांक 09.07.19 उक्त याचिका श्रीमान न्यायालय कके समक्ष प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में जानकारी की दिनांक से प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत याचिका निर्धारित समायवधि में प्रस्तुत की हुई है। इसी प्रकार माननीय राज. उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका सं. 4411/2013 अनवान प्रमोद बागरा बनाम राजस्व मंडल अजमेर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 3.11.16 में भी 45 वर्ष पश्चात प्रस्तुत प्रकरण को जानकारी की दिनांक से मियाद में शुमार किया गया है। माननीय राज. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि जहां किसी प्रकरण में मेरिट को देखा जाना आवश्यक है तथा प्रार्थी के हितों पर कुठाराघात हो रहा है, वहां पर न्यायालय मियाद के बन्दु को नजर अंदाज करेगा तथा प्रकरण में मेरिट पर निर्णय पारित करेगा। उक्त प्रकरण में भी निगरानीधीन पट्टा प्रार्थी की पट्टासुदा भूमि पर सभी नियमों को दरकिनार करते हुए तत्कालीन सरपंच से मिली भगत करके पश्चातवर्ती तारीखों में जारी किया हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रकरण अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा प्रार्थी के प्रकरण को मियाद में शुमार कर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है।

2(10)-अप्रार्थी के द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत करते हुए जो तथ्य अंकित किये हैं, उनसे यह कतई साबित नहीं होता है कि प्रार्थी को प्रारंभ से ही यानि की पट्टा जारी करने की दिनांक से ही विवादित पट्टे की जानकारी हो, जहां तक अप्रार्थी के द्वारा विवादित भूखण्ड के पते के राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बिजली टेलीफोन के बिल आदि प्रस्तुत किये हैं, उस संबंध में यह तथ्य न्यायालय हाजा को अवगत करवाना आवश्यक है कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण के जवाब से पूर्व ही न्यायालय हाजा के समक्ष अपने निगरानी प्रार्थना पत्र में यह तथ्य वर्णित कर दिये गये हैं, प्रार्थी के निगरानी प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया हुआ है कि अप्रार्थी सं. 2 व 3 की माता श्रीमती केसर देवी प्रार्थी की पुश्तैनी पट्टासुदा भूमि में ही निवास करती थी, क्योंकि श्रीमती केसर देवी की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इस कारण श्रीमती केसर देवी प्रार्थी के दादा के यहां घरेलू कार्य करती थी और प्रार्थी के दादा ने केसर देवी को रहवास हेतु अपने पट्टा सुदा जायदाद में दो कमरे बनाकर प्रार्थी के मकान की पश्चिमी दिशा में स्थित रिक्त पडी भूमि दी गई थी। इस कारण अप्रार्थी सं. 2 व 3 के रहवास के पते के दस्तावेज प्रार्थी के पट्टासुद सम्पत्ति के पते के होना संभव है। इस आधार पर अप्रार्थी सं. 2 व 3 मात्र उक्त दस्तावेजों के आधार पर यह तथ्य साबित नहीं कर सकते कि उनके पते उक्त विवादित सम्पत्ति के होने के कारण विवादित सम्पत्ति पर उनका जायज हक हो और उन्हें इस विवादित सम्पत्ति का पट्टा प्राप्त करने का हक हो। जो तथ्य अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने अपने जवाब प्रार्थना में वर्णित किये हैं, वह तथ्य तो प्रार्थी के द्वारा निगरानी याचिका में पूर्व में ही वर्णित कर दिये थे, इस कारण प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 2 व 3 की माता के नाम जारी पट्टे को खारिज किया जाना न्यायोचित है। साथ ही इस संबंध में माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा रिट याचिका सं. 7714/12 अनवान पाकाराम बनाम राज. राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.04.13 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति का 50 वर्ष से अधिक पुराना भी रहवास आया हुआ है और यदि उक्त रहवास के आधार पर पट्टा जारी किया गया है तो रहवास पट्टा जारी



करने का आधार नहीं हो सकता है, उक्त प्रकरण में भी अप्रार्थी सं. 2 व 3 के द्वारा अपने पुराने रहवास के आधार पर पट्टा प्राप्त करने का तथ्य जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है, जबकि अप्रार्थी सं. 2 व 3 का रहवास मात्र कामगार की हैसियत से था। इस कारण अप्रार्थी सं. 2 व 3 की माता के नाम से जारी पट्टा अपास्त किये जाने योग्य है।

2(11)—प्रार्थी के द्वारा अपनी निगरानी याचिका में यह भी वर्णित किया गया था कि अप्रार्थी सं. 2 व 3 की माता के नाम से जारी पट्टा विलेख, तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत गोरेडी चांचा, पंचायत समिति डेगाना, जिला नागौर से मिली भगत करके पूर्ववर्ती तारीखों में जारी किया हुआ है। जिसकी न तो कोई मिसल संधारित की गई है, न ही प्रस्ताव रजिस्टर में इसका इन्द्राज है। मात्र पट्टे पर तत्कालीन सरपंच के द्वारा मोहर लगाकर फर्जी मिसल नंबर एवं फर्जी पट्टा नंबर अंकित कर पट्टा जारी किया गया है, जिसके पुष्टि नगर पालिका डेगाना अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये गये रिकॉर्ड से होती है। अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष जो रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है, उसमें मात्र पट्टे की एक प्रति ही है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नगर पालिका के यहां जमा नहीं होना, अपने जवाब में वर्णित किया गया है, इससे यह तथ्य भली भांति साबित होता है कि राज. पंचायत राज अधि. 1996 के नियम 146 से 152 में पट्टा जारी करने की जो प्रक्रिया वर्णित की गई है, उसका पालन तत्कालीन ग्राम पंचायत गोरेडीचांचा के द्वारा नहीं किया गया था, उक्त नियमों के अनुसार नियम 146 में प्रार्थना पत्र देना उसके साथ नक्शा संलग्न करना, इस बाबत राशि जमा करना तत्पश्चात् नियम 147 के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र को ग्राम सेवक के द्वारा रजिस्टर्ड सं. 21 में इन्द्राज करना तत्पश्चात् ग्राम सेवक के द्वारा उक्त समस्त कार्यवाही को पंचायत की आगामी बैठक में रखना और उक्त बैठक में मौका स्थल का निरीक्षण करने हेतु तीन वार्ड पंचान की कमेटी गठित करना, उक्त पंचान की कमेटी से आशय की रिपोर्ट प्राप्त होना कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि गांव के किसी सार्वजनिक कार्य हेतु उपयोग व उपभोग में नहीं जा रही है, उक्त भूमि से गांव के किसी भी व्यक्ति का सुखाधिकार प्रभावित नहीं हो रहा है, उक्त भूमि किसी रास्ते के उपयोग में नहीं आ रही है, इस प्रकार की सकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् उसे पुनः पंचायत की बैठक में रखी जाकर उक्त भूमि के पट्टे देने बाबत 15 दिवस की आपत्ति आमंत्रित प्रस्तुत करने हेतु नोटिस देने के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं प्रस्तुत होने पर निर्धारित शुल्क लेकर पट्टा जारी किया जाना नियमों में वर्णित किया गया है, किन्तु तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम सचिव के द्वारा उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और उक्त पट्टे का न तो मिसल संधारित की गई और न ही इसका किसी प्रस्ताव रजिस्टर में इन्द्राज किया गया, इस प्रकार यह तथ्य भली भांति साबित है कि उक्त पट्टा नियमों को दरकिनार करते हुए अनियमित तरीके से जारी किया हुआ है। माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा रिट याचिका सं. 14332/2015 नारायणलाल बनाम राज. राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.04.17 में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी भी पट्टे को जारी करने में ग्राम पंचायत के द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया है और अनियमित तरीके से पट्टा जारी किया गया है तो वह पट्टा निरस्तनीय है। निगरानी में वर्णित पट्टे में भी किसी भी प्रकार के नियमों का पालन नहीं किये जाने से अप्रार्थी सं. 2 व 3 की माता के नाम से जारी पट्टा निरस्तनीय है। इसके साथ ही माननीय राज. उच्च न्यायालय के द्वारा यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पट्टासुदा भूमि का दुबारा पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। उक्त निगरानीधीन पट्टा भी प्रार्थी के दादा के नाम से जारी पट्टे का दुबारा पट्टा जारी किया हुआ होने से निरस्तनीय है तथा अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एसबी सिविल रिट पिटिशन सं. 4411/13 प्रमोद बागडा बनाम राज. सरकार में निर्णय दिनांक 3.11.16 की फोटोप्रति, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एसबी सिविल रिट पिटिशन सं. 365/17 प्रकाशचंद मीणा बनाम संजय बैराठी में निर्णय दिनांक 19.01.17 की फोटोप्रति, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एसबी सिविल रिट पिटिशन सं. 7774/12 पकाराम बनाम राज. सरकार में निर्णय दिनांक 17.04.13 की फोटोप्रति, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एसबी सिविल रिट पिटिशन सं. 14332/15 नारायणलाल बनाम राज. सरकार में निर्णय दिनांक 13.04.17 की फोटोप्रति तथा Western Law Cases, 2017(2) पेज 138 पेश की गई।

3— वकील अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने अपनी बहस में बताया कि —

3(1)—आराजी भूमि प्रार्थी की पुश्तनी व उसके दादा गंगाधर महेश्वरी के नाम से होने का कथन सर्वथा गलत है तथा प्रार्थी के दादा के यहां अप्रार्थी सं. 2 व 3 की माता केसर देवी घरेलु कार्य करती थी। इसलिये उसके दादा ने केसर देवी को रहवास हेतु उक्त पट्टासुदा भूखण्ड में से सड़क की तरफ का भूखण्ड रहने के लिये दिया गया हो, यह गलत होने से अस्वीकार है।

3(2)—प्रार्थी ने आज से करीबन 20 वर्ष पहले जारी हुए पट्टे को इस निगरानी के माध्यम से चुनौती दी है जो निगरानी प्रथम दृष्टया मियाद बाहर होने के कारण केवल मात्र इस आधार पर ही खारिज किये जाने योग्य है। यहां पर यह कथन करना प्रासंगिक रहेगा कि उक्त प्रार्थी जो डेगाना का निवासी है तथा वादग्रस्त भूमि के पास ही अपना मकान होना बता रहा है, वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 का अपने माता पिता के जीवन काल से पिछले करीबन 70-80 सालों से ज्यादा समय से निरंतर शांति पूर्वक कब्जा है। विदित रहे कि उक्त जायगा के



एक हिस्से पर पुराना मकाना बना हुआ है तथा कुछ हिस्से पर जो नव निर्माण किया जा रहा है वह नव निर्माण पिछले 6-7 माह से ज्यादा समय से मौके पर चल रहा है। ऐसी स्थिति में जब अप्रार्थी सं. 2 व 3 व उसके माता पिता का वादग्रस्त भूमि पर पिछले 70-80 वर्षों से शांतिपूर्वक रहवास व स्वामित्व है जो एलानियां तौर पर डेगाना के हर वासी को पता है तो ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं. 2 द्वारा निर्माण कार्य शुरू करने पर प्रार्थी को उक्त पट्टे की सर्वप्रथम जानकारी होने का कथन पूर्णतया कपोल कल्पित व झूठा कथन है जिस पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता। उक्त जायगा पर जो मकान बना हुआ है उस मकान पर वर्ष 1989 से विद्युत कनेक्शन अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पिता के नाम से तथा जल कनेक्शन अप्रार्थी सं. 2 व 3 की माता के नाम से तथा टेलीफोन कनेक्शन अप्रार्थी सं. 3 के नाम से मौके पर लगा हुआ है।

3(3)-वादग्रस्त भूमि का पट्टा जारी होने के पश्चात इसका एक वसीयतनामा अप्रार्थी सं. 2 व 3 की माता ने अप्रार्थी सं. 2 व 3 के हक में लिखा उसके पश्चात उक्त वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण नगरपालिका मंडल डेगाना द्वारा अप्रार्थी सं. 3 के हक में जरिये आदेश क्रमांक नपा/डेगाना/2018-19/1295 दिनांक 11.1.19 के द्वारा स्वीकृत हुआ है। इस प्रकार से वादग्रस्त भूमि के संबंध में जो भी दस्तावेजात है वह अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पास वैध उचित साधिकार एवं प्रभावपूर्वक है।

3(4)-इस प्रकार से प्रार्थी को उक्त पट्टे के बारे में जारी होने की तिथि से लेकर आज दिन तक जानकारी रही है यहां तक कि नगरपालिका डेगाना में जो नामान्तरकरण की कार्यवाही हुई उसमें भी सार्वजनिक रूप से आपत्ति - विज्ञापित जारी हुई थी उस समय भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रार्थी द्वारा नहीं की गई है।

3(5)-उक्त प्रकरण में मौके पर जो निर्माण कार्य हो रहा है 70-80 वर्षों से भी पहले से ही पुराना हो रहा है जिसमें समय समय पर नव निर्माण एवं मरम्मत की जाती रही है, हाल ही में इस नव निर्माण की अनुपालना में मौके पर जो निर्माण कार्य हो रहा है जो पिछले 6-7 माह से ज्यादा समय से हो रहा है। इस अवधि में प्रार्थी द्वारा कहीं पर भी कोई शिकायत आपत्ति नहीं की गई है जो निर्माण कार्य भूतल का पूर्ण होकर प्रथम मंजिल की छत डल रही है उस समय अचानक प्रार्थी का बोलना इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि प्रार्थी येनकेन प्रकारेण अप्रार्थी सं. 2 व 3 को तंग व परेशान करने में लगा हुआ है। महज में तंग व परेशान करने के उद्देश्य से उक्त कार्यवाही अप्रार्थी सं. 2 व 3 विरुद्ध पेश की है। जो प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है।

3(6)-अभ्यस्ता के सिद्धान्त के आधार पर भी प्रार्थी का उक्त आवेदन पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

3(7)-निगरानी में किसी प्रकार का कोई निर्माण संबंधी यथास्थिति बाबत विधि अनुसार कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

3(8)-उक्त प्रकरण में पट्टा जारीकर्ता ग्राम पंचायत डेगाना को पक्षकार नहीं बनाया है। इसलिये पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर उक्त निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

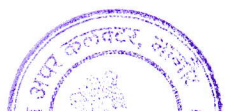
3(9)-उक्त प्रकरण में भूमि की कीमते बढ़ जाने पर नाजायज रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से व्यक्ति विशेष के इशारों पर इस प्रकार के कार्यवाही किये जाने का प्रचलन बढ़ा है। जिसकी परिणति यह निगरानी है।

3(10)-उक्त प्रकरण में प्रार्थी की ओर से जो लिखित बहस प्रस्तुत की गई है वह लिखित बहस की परिभाषा में नहीं आती। क्योंकि बहस में तो केवल विवाद के बिन्दु उठाये जाते हैं और ऐसे विवाद के बिन्दुओं के लिये किसी भी पक्ष को क्या कहना है यह स्पष्ट किया जाता है। जबकि प्रार्थी द्वारा जो लिखित बहस प्रस्तुत की गई है उस बहस में केवल मात्र निगरानी के तथ्यों की पुनरावृत्ति मात्र की गई है जो केवल मात्र न्यायालय हाजा को गुमराह करने के अलावा कुछ भी नहीं है।

3(11)-निगरानी में केवल मात्र किसी प्रस्ताव एवं आदेश की वैधता, शुद्धता एवं औचित्यता को देखा जाता है। तथ्यों पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में जो पट्टा जारी हुआ है, उसके लिये जो प्रस्ताव एवं आदेश हुए हैं उनमें क्या अवैधता है, क्या शुद्धता है एवं क्या औचित्यता नहीं है, को देखा जाना है। इस संबंध में प्रार्थी की ओर से लेस मात्र ऐसी विधिक व्यवस्था नहीं बतायी गई है जिसके कारण उक्त पारित प्रस्ताव एवं आदेश के संबंध में कोई अवैधता हो।

3(12)-प्रार्थी पक्ष की ओर से पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत बने नियम 1996 के नियम 146 से 152 तक में वर्णित कौनसे प्रावधानों की पालना हस्तगत पट्टा जारी करने में नहीं हुई है, के बारे में किंचित मात्र भी वर्णन नहीं है। जब ऐसा कोई वर्णन नहीं है तो यह कैसे मान लिया जावे कि उक्त पट्टा जारी करने के संबंध में किन्हीं नियमों की पालना नहीं हुई है। यहां पर यह कथन करना भी प्रासंगिक रहेगा कि एक तरफ तो प्रार्थी यह बात कह रहा है कि उक्त पट्टा जारी करने के संबंध में नियम 146 से 152 की पालना नहीं होना बताया गया है। यह दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। क्योंकि बकौल प्रार्थी के जब मिसल का अस्तित्व नहीं है और मिसल ही नहीं तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को इस बात का कैसे आभास हो गया कि नियम 146 से 152 की पालना नहीं हुई है। यह केवल मात्र प्रार्थी धूल में लट्ट मार रहा है। इस आधार पर यह बखूबी साबित है कि उक्त पट्टा जारी होने के संबंध में विधि की तमाम प्रक्रियाओं की पालना हुई है। इसलिये उक्त पट्टे को किसी भी रूप या प्रकार से खारिज नहीं किया जा सकता।

3(13)-उक्त प्रकरण में बड़ी ही हास्यास्पद स्थिति है कि लिखित बहस में प्रार्थी राज. पंचायती राज अधिनियम



(Signature)
आयुक्त कमिश्नर नागौर

1996 के नियम 146 से 152 की व्याख्या करके न्यायालय हाजा को गुमराह करने का ऐसा प्रयास किया है कि जैसे सारा पट्टा ही फर्जी जारी हो रखा है। वस्तुतः इस मद में प्रार्थी ने उक्त नियमों में क्या व्यवस्था दे रखी है उसका उल्लेख कर दिया है, परंतु उस दी गई व्यवस्था में से किन नियमों की पालना हस्तगत पट्टा जारी होने के संबंध में नहीं हुई है, के बारे में लेस मात्र भी अंकन नहीं है। ऐसा अंकन हो भी कैसे सकता है जब बकोल प्रार्थी के उक्त पट्टा की उसे मिसल नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी क्या भगवान हैं जो छड़ी घुमाकर ऐसे नियमों की पालना नहीं होने के बारे में जानकारी कर लेगा।

3(14)—उक्त प्रकरण में जो विषय वस्तु विवाद की लेकर आया है वह विषय वस्तु निगरानी की विषय वस्तु नहीं हो सकती। क्योंकि प्रार्थी एक भू भाग के स्वामित्व के विवाद को लेकर न्यायालय हाजा के समक्ष आया है ऐसे स्वामित्व का विवाद जैसे कि क्या प्रार्थी का पट्टा वादग्रस्त भूमि का है, क्या उक्त भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की रही है एवं क्या उक्त भूमि प्रार्थी के बडे़रो के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 व 3 के बडे़रो को दी गई थी, यह सभी ऐसे प्रश्न हैं जिनका निस्तारण दीवानी न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। इनका निस्तारण न तो निगरानी की विषय वस्तु हो सकती है एवं न ही ऐसे प्रश्नों को निगरानी में तय किया जा सकता है।

3(15)—उक्त निगरानी की जो विषय वस्तु है उसके लिये तो धारा 34, 37 व 38 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1965 के अन्तर्गत दीवानी न्यायालय ही अपना कोई निष्कर्ष दे सकते हैं, निगरानी में इस बिन्दु पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता।

3(16)—उक्त जायगा पर जो मकान बना हुआ है उस मकान पर वर्ष 1989 से विद्युत कनेक्शन अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पिता के नाम से तथा जल कनेक्शन अप्रार्थी सं. 2 व 3 की माता के नाम से एवं टेलीफोन कनेक्शन अप्रार्थी सं. 3 के नाम से मौके पर लगा हुआ है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के समर्थन में डीएनजे 2012(2) पेज 603, डीएनजे 2009(1) पेज 194, डीएनजे 2008(2) पेज 736, डीएनजे 2002(1) पेज 307, आरबीजे 2012 पेज 686, आरआरडी 2011 पेज 228, आरबीजे 2011 पेज 352, आरबीजे 2010 पेज 289, आरबीजे 2010 पेज 628, आरआरडी 2009 पेज 150, आरआरडी 2009 पेज 661, आरआरडी 2008 पेज 817, डीएनजे 2003(3) पेज 1266, आरआरडी 2002 पेज 26 तथा आरआरडी 2001 पेज 35 नजीरे प्रस्तुत की है।

4— वकील अप्रार्थी सं. 1 ने अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका डेगाना की ओर से बहस करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत गोरेडी चांचा द्वारा पट्टा जैर निगरानी जारी किया गया है। उक्त क्षेत्र नगरपालिका डेगाना गठित हो जाने से वर्तमान में नगरपालिका क्षेत्र में स्थित है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा नगरपालिका को सुपुर्द किया गया है। जो विधिअनुसार सही है एवं विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जारी किये गये पट्टे पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इसलिये प्रार्थी की निगरानी निरस्त की जानी चाहिये।

5— पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार—

5(1)— प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत गोरेडी चांचा पंचायत समिति डेगाना की मिसल सं. 396/2001-02 दायर दिनांक 05.04.01 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की माता केसर देवी के पक्ष में जारी पट्टा सं. 125 दिनांक 24.12.2001 जारी किया गया है, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

5(2)— प्रार्थी द्वारा पट्टा जैर निगरानी जारी करने से पूर्व पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 146 से 152 में पट्टा जारी करने की जो प्रक्रिया वर्णित की गई है। उसका तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा पालन नहीं किया गया है तथा ऐसी कोई पत्रावली कायम ही नहीं की गई है, कथन किया गया है। नगरपालिका डेगाना के पत्र दिनांक 23.7.19 के द्वारा मूल पट्टा सं. 125 भिजवाया गया है तथा इससे संबंधित पत्रावली ग्राम पंचायत गोरेडीचांचा द्वारा सुपुर्द नहीं किया जाना बताया गया है। जिससे हालांकि मूल पत्रावली रिकार्ड पर नहीं आयी है परंतु ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा सं. 125 जैर निगरानी के अवलोकन से भूमि की कीमत रसीद सं. 59 (62) दिनांक 24.12.01 को जमा होना व ग्राम पंचायत के संकल्प सं. 8/XIV दिनांक 05.12.01 लिया जाकर इसकी पालना में पट्टा जारी होना प्रतीत होता है।

5(3)— प्रार्थी द्वारा आराजी भूमि का पट्टा उसके दादा गंगाधर के पक्ष में तहसीलदार द्वारा दिनांक 24.03.53 को जारी होना बताते हुए विवादित जगह अप्रार्थी सं. 2 व 3 की माता केसर देवी उसके दादा के घरेलु कार्य करने की वजह से निर्मित कमरा व भूखण्ड रहवास हेतु देने का कथन किया गया है। इससे यह तथ्य भी स्थापित होता है कि अप्रार्थी वर्षों से प्रश्नगत भू-खण्ड पर काबिज है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोज के अनुसार प्रथम मंजिल का निर्माण हो चुका है तथा पट्टा सं. 125 दिनांक 24.12.01 यानि 18 वर्ष पहले ही जारी हो चुका है तथा इसी क्षेत्र का परिवार कार्ड 01.11.95 से भी अप्रार्थीगण का आराजी पर पुराना कब्जा होना प्रकट करता है। जिससे प्रथम दृष्टि से ही मामला प्रार्थी के पक्ष में रिकार्ड से साबित नहीं है।

ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

6— उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

7— निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मनोज कुमार)

आपस कलक्टर, नोएडा